सुरक्षा प्रणालियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय मिशन

1830. **डा० महेश चन्द्र शर्मा:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सुरक्षा प्रणालियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दस वर्षीय राष्ट्रीय मिशन क्या है;

(ख) इसकी प्रगति कैसी है; और

(ग) इस मिशन का दस वर्षीय कार्यकाल किस वर्ष पूरा होने की संभावना है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन० वी० एन० सोमू): (क) रक्षा प्रणालियों में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए वर्ष 1995 में दस वर्षीय राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया है ताकि वार्षिक रक्षा अर्जनों में स्वदेशी अंश को 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 70 प्रतिशत किया जा सके।

(ख) सक्षम और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए इस मिशन के तहत की गई प्रारंभिक कार्रवाइयों में उत्कृष्ट प्रगति हुई है। मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन 5.56 मि०मी० लघु शस्त्र, वायुसेना के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली, सतह से सतह पर मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र "पृथ्वी" और पायलट रहित लक्ष्यभेदी वायुयान "लक्ष्य आदि का सफलतापूर्वक विकास करके उत्पादन किए जाने के परिणामस्वरूप रक्षा अर्जनों में स्वदेशी अंश काफी अधिक बढ़ जाएगा।

(ग) रक्षा प्रणालियों के मामले में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने से संबंधित दस वर्षीय मिशन 2005 में पूरा हो जाएगा।

Setting up of Court Martial Administrative Tribunal

1831. SHRIMATI JAYANTI PATNAIK: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether Government have a proposal to set up Armed Forces Court martial Administrative Tribunal;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) the number of cases pending pertaining to Armed Forces; and

(d) the steps taken to settle those pending cases?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI N.V.N. SOMU): (a) to (d) A proposal to set up Armed Forces Administrative and Court Martial Tribunal is currently under consideration of the Government. There are 4238 cases pending for decisions in various courts of India. The progress of these cases are monitored by the concerned Authorities from time to time.

Purchase of spurious spare parts by army repair units

1832. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the army repair units in the country are flooded with spurious spare parts for its B class vehicles, thus crippling the maintenance of the vehicles being used by the field units;

(b) if so, whether Government have made any inquiry into the matter;

(c) if so, the details thereof; and

(d) the action taken by Government in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI N.V.N. SOMU): (a) No, Sir. There is a well laid down procedure for purchase of spare parts from recognised suppliers.

(b) to (d) Not applicable in view of (a) above.

विमानों के तकनीकी खामियों के अध्ययन के लिए समिति

1833. **श्री अखिलेश दास:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 1996 के दौरान वायुसेना की विमान दुर्घटनाओं में वृद्धि के कारण सरकार ने तकनीकी खामियों का पता लगाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है;

(ख) क्या उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और